www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 996 || लखनऊ
शुक्रवार
30 जनवरी 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:53
सूर्यास्तः 05:47
अधिकतमः 21°00
न्यूनतमः 10°00

» पेज 03

विशेष समाचार वैश्विक समस्याओं का समाधान ... >> पेज 02 | एलडीए बनाएगा 27 मंजिला अपार्टमेंट ... >>पेज 04 | समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से ...

12 लाख शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक फ्री इलाज

29 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कैशलेस इलाज से लेकर फेलोशिप युवाओं तक को राहत

फैसला

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्ताव पास किए गए। सबसे बड़ा फैसला यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और कर्मचारियों को लेकर हुआ। ये अब 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज करा पाएंगे। माध्यमिक, बेसिक के साथ ही एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी। इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा, मेरठ के मवाना गोसाईं में 107 बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवार को बसाया जाएगा। शिक्षामंत्री संदीप सिंह ने बताया- बेसिक के 4 लाख 34 हजार

226 टीचर, एडेड के 13 हजार 380 टीचर, सेल्फ फाइनेंस के 4 लाख 72 हजार 735 टीचर, 1 लाख 42 हजार 928 शिक्षामित्र, 24 हजार 417 अनुदेशक, 7 हजार 479 कस्तूरबा गांधी के वार्डन, 97 लाख 344 रसोइया, 2,581 विशेष शिक्षक को फायदा मिलेगा। दरअसल, योगी सरकार का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले आज बैबिनेट की बैठक में बड़े प्रस्ताव पास किए गए। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया- 2 लाख 97 हजार 589 माध्यमिक टीचर्स को भी कैशलेस का फायदा मिलेगा।

>> (शेष पेज 04 पर)

अब आधार कार्ड से रुकेगी फर्जी रजिस्ट्री

संपत्ति पंजीकरण में छद्म व्यक्तियों (फर्जी) द्वारा की जाने वाली रजिस्ट्री को रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत आधार संख्या धारकों की पहचान e-KYC के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थापित करने और इलेक्ट्रॉनिक/आधार ई-हस्ताक्षर को ई-निष्पादन की परिभाषा में सम्मिलित किया गया। यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू की जाएगी। इससे पक्षकारों और गवाहों की पहचान का सत्यापन होगा।

कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए

- मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997: नई कर अधिसूचनाएं जारी, राजस्व बढ़ाने और परिवहन कर सुधार हेतु।
- विज्ञान पार्क व नक्षत्रशालाः बरेली और मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाया गया।
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर): भविष्य के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव पास।
  नोएडा मेट्रोपोलेटिन कॉरपोरेशनः सुप्रीम कोर्ट आदेश के तहत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा गठन।
- अमृत-2.0 योजना (सीवरेज):
  गोरखपुर: 17 वार्डों में 721.40 करोड़ रुपये खर्च।
  वाराणसी: 18 प्रभावित वार्डों में 266.49 करोड़ रुपये खर्च।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020: संशोधन प्रस्ताव पास।
- देवरिया राज्य मार्ग 79: 31.5 किमी सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति।
- पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशनः उप निबन्धक कार्यालयों में लागू किया जाएगा।
- उप खनिज रायल्टी और डेडरेटः उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में द्वितीय संशोधन।
- बहराइच में आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वासः ग्राम भरधापुर में भूमि व्यवस्था और अवस्थापना सुविधाएं।
- बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्वासः सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी-सीएम बन सकती हैं

पति की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, पार्टी के शरद गुट में विलय की भी चर्चा

तमसा संकेत, एजेंसी

मुंबई। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी CM बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं, वे अब अजित पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इस प्रस्ताव पर एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। उधर एनसीपी पार्टी का शरद गुट से भी विलय हो सकता है। दरअसल अजित पवार का बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हुई। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा

गया है। केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह प्लेन को वापस ऊंचाई पर ले गया। दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। विमानन कंपनी VSR वेंचर्स ने कहा है कि पायलट को 16 हजार घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। विमान की को-पायलट के पास 1500 घंटे का एक्सपीरियंस था।

फास्ट न्यूज

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों की नसबंदी और दूसरी जगह शिफ्ट करने के 7 नवंबर के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार हर दिन सिर्फ 100 आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रही है जो नाकाफी है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने कोर्ट के निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया है।

रील बनाने से मना किया तो पति को मार डाला

झाबुआ। झाबुआ में पत्नी बारात में रील नहीं बनाने देने पर इस कदर नाराज हुई कि पति की हत्या कर दी। वह भी शादी की पगड़ी से गला घोंटकर। इसके लिए यूट्यूब देखकर पूरी प्लानिंग की। वारदात थांदला थाना इलाके में 28 जनवरी की है। पुलिस ने मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए नाबालिग पत्नी को अभिरक्षा में ले लिया है। एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने बताया कि 28 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे डायल 112 पर सूचना मिली थी कि 25 वर्षीय कैलाश पिता रायचंद माल का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस को शुरुआती जांच में मामला उलझा हुआ लगा।

सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बने

चंडीगढ। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत हुई है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर अब BJP का कब्जा हो गया है। नए मेयर सौरभ जोशी बन गए हैं। सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा चुने गए। मेयर चुनाव में भाजपा को 18 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को सात और आप उम्मीदवार को 11 वोट मिले है।

एसआईआर के खिलाफ सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

याचिकाकर्ता बोले- ईसीआई मनमानी नहीं कर सकता, चुनाव अधिकारी अदालत नहीं जो नागरिकता तय करेंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग (ECI) को SIR प्रक्रिया में सभी राज्यों में नियमों का सही ढंग से पालन करना चाहिए। तमिलनाडु में जिन लोगों का नाम स्पेलिंग एरर के चलते काटा गया है। उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, सब-डिवीजन के तालुका ऑफिस और शहरी इलाकों के वार्ड ऑफिस में लगाई जाए। उधर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि नई वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश में महिलाओं के नाम कट रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गरीब और कमजोर लोगों

पर बोझ डाला गया। वोटर को खुद फॉर्म भरने की जिम्मेदारी दी गई है। जो अनपढ़ हैं या प्रवासी हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता है। चुनाव अधिकारी यह कैसे तय कर सकता है कि कोई नागरिक है या नहीं? वे कोई अदालत नहीं है। अगर विवाद हो तो जिरह का मौका मिलना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा- वोटर लिस्ट की जांच करना न्यायसंगत और सही है। कोर्ट को इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। द्विवेदी ने आगे कहा कि कुछ NGO और नेताओं के कहने पर हर मामले की जांच नहीं हो सकती। बिहार में जिन 66 लाख लोगों के नाम हटे हैं, उनमें से किसी ने कोर्ट में शिकायत नहीं की। आजकल ECI को गाली देकर चुनाव जीतना फैशन बन गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(SIR) प्रक्रिया में जिनके नाम कटे हैं, अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे किसी एक मामले के तथ्यों को उठाकर उन्हें किसी दूसरे राज्य की SIR प्रक्रिया पर लागू करना गलत होगा।

मीडिया वाले मुझसे जलते हैं : मंत्री विजय शाह

खंडवा। जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह ने कहा है कि मीडिया वाले उनसे जलते हैं। शाह ने यह बात गुरुवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। मंत्री शाह बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का जिक्र किया। बताया कि उनके विभाग ने इस साल 14 बच्चों की फीस चुकाई है। इनमें से प्रत्येक को 37-37 लाख रुपए दिए गए हैं। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर तंज भी कसा। जब डीन डॉ. संजय दादू ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए आईटीआई कॉलेज के पीछे 14 एकड़ जमीन आवंटित है लेकिन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है। इस पर मंत्री शाह ने कहा- आपने 6 साल बाद जाकर इस डाकिये को बुलाया है। अब यह डाकिया आपकी मांग को सरकार तक भिजवाएगा। इस कॉलेज का नामकरण पूर्व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के नाम से है।

विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई

तीनों सेनाओं और सीएपीएफ के बैंड ने धुनें पेश कीं

समापन

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के विजय चौक पर गुरुवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चले कार्यक्रमों का समापन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेरेमनी में मौजूद रहीं। समारोह की शुरुआत में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआत धुन 'कदम-कदम बढ़ाए जा' बजाकर की। तीनों सेनाओं के साथ CAPF के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने भारतीय धुनें बजाईं।

वायुसेना के बैंड ने पिछले साल रिटायर किए गए फाइटर जेट MIG-21 की आकृति बनाई। वहीं नौसेना बैंड ने वंदे मातरम् की 150वीं सालगिरह के मौके पर 3 आकृतियां बनाईं। समारोह में उपराष्ट्र-पति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित अन्य केंद्रीय मंत्री और आम नागरिक मौजूद रहे।

>> (शेष पेज 04 पर)

केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश, देशभर में नियमों का विरोध

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। UGC ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देशभर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के UGC नियम देशभर में लागू रहेंगे। UGC के नए कानून का नाम है- 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026।' इसके

"छात्रों ने बताया कि नए बिल में अपील के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था. यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट के आधार पर फैसला लिया जाता, तो उसके खिलाफ अपील का कोई रास्ता नहीं बचता. इसके अलावा कमेटी गठन और पीड़ित की परिभाषा को लेकर भी गंभीर आपत्तियां थीं, जिसमें सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था.

छात्रों ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार

छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि किसी भी उपयोगी कानून का यदि दुरुपयोग होने लगे, तो उस पर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है. कोर्ट का यह आदेश उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, न्याय और एकता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

अपील का कोई प्रभावी विकल्प नहीं था

वहीं छात्र निशांत तिवारी ने कहा कि यदि एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लोग शिकायत करते, तो सवर्ण वर्ग के छात्रों के पास अपील का कोई प्रभावी विकल्प नहीं था. सुप्रीम कोर्ट की रोक से फिलहाल सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है. उन्होंने कहा कि इस निर्णय का वे स्वागत करते हैं और सरकार से संतुलित और न्यायपूर्ण कानून लाने की अपेक्षा रखते हैं.

छात्रों में बढ़ रही थी आशंका

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र अविरल सिंह ठाकुर ने लोकल 18 से कहा कि इस बिल का लगातार विरोध सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा किया जा रहा था.

"अविरल सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि इस बिल से सामान्य और आरक्षित वर्ग के छात्रों के बीच अनावश्यक विरोधाभास और ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही थी. उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि इस तरह के कठोर प्रावधानों की आवश्यकता थी.

सुप्रीम कोर्ट के 4 अहम कमेंट्स-

- *कोर्ट ने पूछा कि जब 'भेदभाव' की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो 'जाति-आधारित भेदभाव' को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी?*
- *कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि यह कैंपस में एक बड़ी समस्या है।*
- *सीजेआई ने कहा- अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जातिविहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं?*
- *सीजेआई ने अलग-अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा- भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते थे, आज इंटर-कास्ट मैरिज भी होती हैं। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए।*

संबोधन : सदन में जवाब नहीं देते, संसद के बाहर पीएम बोले थे- हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी

बजट सत्र से पहले मोदी की बातें दिखावटी : जयराम रमेश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। पीएम ने गुरुवार को कहा, 'हमारी सरकार की पहचान रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा, 'यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 25 साल बहुत अहम हैं।' पीएम के

इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि, पीएम ने हर बार की तरह देश के नाम दिखावटी मैसेज दिया। हमें यही उम्मीद थी।

>> (शेष पेज 04 पर)

पीएम ने कहा- आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आशा की किरण

पीएम मोदी ने कहा,'वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, 'आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र बना है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच समझौता हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारत के जो मैन्यूफैक्चरर है।

कांग्रेस सांसद का आरोप- मनरेगा का गला घोंटा जा रहा

मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने कहा, 'जब यूपीए ने मनरेगा की शुरुआत की थी, तब यह काम का अधिकार देने वाली योजना थी और रोजगार की गारंटी देती थी। अब इसके लिए आवंटित धन में कटौती कर दी गई है और राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, जिससे इस योजना का गला घोंटा जा रहा है और इसे समाप्त करने की स्थिति पैदा हो गई है।'

पीएम ने कहा- अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर बाजार में जाएं

पीएम ने कहा, 'मेरे देश के मैन्यूफैक्चरर के लिए यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा बाजार खुल गया है। अब सस्ते में हमारा माल वहां पहुंचेगा।

"पीएम मोदी ने कहा, 'देश का ध्यान बजट की तरफ होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार कि पहचान रही है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफोर्म। सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस तरफ लगातार काम कर रहे हैं। हमारे हर निर्णय में देश की प्रगति लक्ष्य है। हमारे सारे फैसले ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हमारे योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक हैं। हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, लेकिन साथ-साथ हम मानव केंद्रित व्यवस्था को कम नहीं आंकेंगे। भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफिक से आज दुनिया की बहुत बड़ी उम्मीद है। विश्व इसका जरूर स्वागत करता है और स्वीकार भी करता है। देश आज आगे बढ़ रहा है। देश आज व्यवधान का नहीं, समाधान की तरफ बढ़ रहा है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोकर बैठने की नहीं, हिम्मत के साथ समाधान वाले फैसले लेने की है।

शादी के बाद साथ नहीं रहे तो रजिस्ट्रेशन औपचारिकता : हाइकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद अगर पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं तो शादी की रजिस्ट्रेशन एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की डिवीजन बेंच ने कहा कि इसका इस्तेमाल एक साल में तलाक लेने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता। हाइकोर्ट बुधवार को एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शादी की तारीख से एक साल पूरा होने से पहले आपसी सहमति से तलाक के लिए ज्वाइंट याचिका पेश करने की अनुमति खारिज कर दी गई थी। याचिका में कहा गया कि दोनों पक्ष कभी एक दिन भी साथ नहीं रहे, शादी कभी पूरी नहीं हुई, और दोनों शादी के तुरंत बाद अपने-अपने माता-पिता के घरों में अलग-अलग रहने लगे। फैमिली कोर्ट ने HMA की धारा 14 के तहत तलाक की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

पार्टी में मतभेदों के बीच थरूर खड़गे-राहुल से मिले

कहा- सब साथ मिलकर काम कर रहे, केरल चुनाव की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे

मुलाकात

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस में पार्टी हाईकमान से मतभेद की खबरों के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। तीनों के बीच बैठक संसद में खड़गे के कार्यालय में हुई। मुलाकात के बाद थरूर ने कहा कि मेरी पार्टी के दोनों नेताओं से बातचीत हुई। सब ठीक है। हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई, जब थरूर और पार्टी लीडरशिप के बीच कुछ मतभेद सामने आए थे। हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर AICC की एक बैठक हुई थी, जिसमें

खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने ये तस्वीर शेयर की है।

थरूर शामिल नहीं हुए थे। वहीं केरल का CM बनने के सवाल पर थरूर ने कहा कि मेरी इस बारे में कभी बात नहीं हुई। मुझे किसी भी चीज के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

>> (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

अजित पवार के जाने के बाद का गुणा-भाग

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। उनके यूं इस तरह चले जाने से समूचा देश स्तब्ध है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा किरदार थे, जिनसे आप असहमत हो सकते हैं, उनके तौर-तरीकों से नाराज हो सकते हैं, उनके समर्थक और मुरीद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उपेक्षित नहीं कर सकते। अजित पवार का सियासी सफर काफी दिलचस्प था। हर दिग्गज नेता की तरह उनकी भी महत्वाकांक्षा शीर्ष पद पर पहुंचने की थी, यानी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना उनका सपना था, जो अब अधूरा रह गया है। अजित पवार मुख्यमंत्री तो एक बार भी नहीं बन पाए, लेकिन छह बार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बनने का रिकार्ड उनके नाम हैं। इसके अलावा कांग्रेस, शिवसेना, भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ वे अलग-अलग मंत्री पद पर भी रहे। इसलिए कहा जाता है कि अजित पवार सत्ता में हमेशा ही बने रहे। अपने चाचा शरद पवार की ऊंगली थामकर अजित पवार ने राजनीति शुरु की, लेकिन बाद में उनसे अलग होकर अपना दबदबा भी दिखाया। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजित पवार महज 23 साल की उम्र में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में शामिल हो गए थे। इसके बाद 1991 में वे पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने और 16 सालों तक इस पद पर काबिज रहे। वे 1991 में ही बारामती से पहली बार सांसद चुने गए। लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने सीट खाली की, इसके बाद 1995 में बारामती से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते फिर 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार विधायक बने रहे। शरद पवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को खड़ा करने और उसे महाराष्ट्र की अग्रणी पार्टियों में शुमार करने में अजित पवार का बड़ा हाथ रहा। लेकिन इस बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के भी राजनीति में सक्रिय होने के बाद अजित पवार अपनी उपेक्षा का दर्द जाहिर करते रहे। एक बार उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मैं शरद पवार का बेटा होता तो मुख्यमंत्री बन जाता। हालांकि चाचा-भतीजे के बीच सीधी तकरार 2022 में देखने मिली। जब अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर अपनी राजनीतिक लकीर खींची और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनावों में एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आए और खबरें थीं कि चाचा-भतीजा के साथ आने से भाजपा को काफी तकलीफ है। लेकिन नगरीय निकाय चुनावों में एनसीपी को बड़ा झटका लगा और उसके कई गढ़ हाथ से निकले भी। इसके बाद अजित पवार जिला पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन उनकी मौत के साथ ही उनकी तैयारियां भी अधूरी रह गईं। करीब 4 दशकों के सियासी सफर में एक बार सांसद और सात बार विधायक रहे अजित पवार ने राज्य सरकार में कई अहम मंत्री पद संभाले। 2010 में वे पहली बार उपमुख्यमंत्री बने और फिर छह बार इसी पद पर काबिज हुए। 2019 में तो दो अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के अधीन उन्होंने उपमुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर 2019 की सुबह उन्होंने देवेंद्र फडनवीस के साथ उपमुख्यमंत्री की शपथ ली। लेकिन, सदन में फडनवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर उपमुख्यमंत्री बनाया गया। आखिरी बार 2024 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बने और उनकी मौत इसी पद पर बने रहते हुए हो गई। सिंचाई घोटाले से लेकर अपनी पार्टी को तोड़ने और भाजपा से हाथ मिलाने जैसे कई विवाद अजित पवार के साथ चस्पां रहे। अब उनकी मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि अजित पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा- 'आज जो हुआ, वह गंभीर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ही विश्वसनीय होगी। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी अन्य एजेंसी पर नहीं।' उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कहा है कि राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती है, पता नहीं अजित पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी। गौरतलब है कि कांग्रेस, एनसीपी और आरजेडी भी विमान हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। खबर ये भी है कि पिछले महीने नगरीय निकाय चुनावों के प्रचार में अजित पवार ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अजित पवार ने 1995 से 1999 के बीच शिवसेना-भाजपा की संयुक्त सरकार में मराठवाड़ा में सिंचाई परियोजना में कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए भाजपा पर आरोप लगाए थे और यहां तक कहा था कि उनके पास इसकी मूल फाइलें हैं। बता दें नगरीय निकाय चुनावों में एनसीपी ने भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ा था। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने दोस्ताना मुकाबले की पहल की थी, लेकिन अजित पवार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। वहीं इन चुनावों में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिला लिए थे। हालांकि एनसीपी के एक साथ आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी। इसके बाद से कयास थे कि अजित पवार फिर से शरद गुट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वे अपना अलग दमखम भी अब तक दिखा चुके थे। लेकिन महायुति टूटती या एनसीपी एक होती, इससे पहले ही अजित पवार का आकस्मिक निधन हो गया।

वैश्विक समस्याओं का समाधान सहयोग से संभव है, टकराव से तो कतई नहीं !

> *वहीं, यूरोप के लिए चीन केवल "ख़तरा" नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। इसलिए अमरीका की यह अपेक्षा कि यूरोप बिना सवाल किए उसकी लाइन पर चले, अब पहले जैसी स्वीकार्य नहीं रही।*

दुनिया का थानेदार अमेरिका और उसका विकल्प बनने की चाहत रखने वाले चीन समेत अन्य विघ्नसंतोषी देशों को शांतिप्रिय व गुटनिरपेक्ष देश भारत ने एक नहीं बल्कि कई बार स्पष्ट कूटनीतिक संदेश दिए हैं कि वैश्विक समस्याओं का समाधान पारस्परिक सहयोग से ही संभव है, टकराव से कतई नहीं लेकिन उनकी शहंशाही प्रवृत्ति है कि मानती नहीं बल्कि तरह तरह से भारत को घेरने या चिढ़ाने की कोशिश करती रहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत ने ऐसे देशों की अनदेखी, अनसुनी करते हुए अपनी सकारात्मक पहलों से अक्सर चौंकाने वाले परिणाम देने शुरू कर दिए हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा और साख दोनों में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। खासकर, वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी और गरीबी का समाधान सहयोग से ही संभव है क्योंकि ये सीमाओं से परे हैं। पारस्परिक युद्धों की तरह इन मुद्दों पर टकराव ऐसी समस्याओं को बढ़ाता ही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय साझेदारी संसाधनों और प्रयासों को एकजुट करती है। यदि पारस्परिक सहयोग के कतिपय प्रमुख उदाहरणों की बात की जाए तो साल 2019 की अंतरराष्ट्रीय महामारी कोविड-19 के वैक्सीन के विकास में वैश्विक सहयोग ने रिकॉर्ड समय में टीके तैयार किए, जैसे COVAX पहल और वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी ने। कहना न होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), Gavi, CEPI और UNICEF के सह-नेतृत्व में COVAX ने COVID-19 टीके 146 देशों को 2 अरब खुराकें वितरित कीं, जिससे निम्न-आय वाले देशों में 2.7 मिलियन मौतें टलीं। इसप्रकार यह पहल वैश्विक महामारी प्रबंधन का एक उत्कृष्ट मॉडल बनी। इससे पहले पेरिस समझौता ने 2015 से ही देशों को एकजुट कर जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने में सफलता पाई जिससे नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बढ़ा। देखा जाए तो जलवायु पर पेरिस समझौता (2015) ने 196 देशों को वैश्विक तापमान वृद्धि 2°C से नीचे रखने के लक्ष्य पर एकजुट किया जिससे नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बढ़ा। यह UNFCCC के तहत बहुपक्षीय सहमति का प्रतीक है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर्यावरण और शांति के लिए विशेष समूह गठित कर साझेदारी को बढ़ावा देते हैं। जहां तक पारस्परिक टकराव के नकारात्मक प्रभाव की बात है तो रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अनाज आपूर्ति बाधित कर 27.6 करोड़ लोगों को भुखमरी की कगार पर पहुंचाया। जबकि सूडान, गाजा और माली जैसे संघर्षों ने 2024 में 14 करोड़ लोगों को भयानक भुखमरी का शिकार बनाया। विशेषकर, शांति स्थापना में UN मिशन अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के 63 शांति अभियान 37 देशों में सक्रिय हैं, जैसे पूर्वी स्लावोनिया (UNTAES) और कोसोवो (UNMIK) में सफल संक्रमणकालीन प्रशासन। इस दिशा में भारत ने 2.9 लाख शांति रक्षक तैनात कर सबसे बड़ा योगदान दिया। जहां तक अन्य क्षेत्रीय सफलताएँ की बात है तो BRICS ने यूक्रेन में मध्यस्थता और गाजा में युद्धविराम के लिए कूटनीति चलाई। जबकि QUAD और ASEAN जैसे मंच सुरक्षा व जलवायु पर सहयोग बढ़ाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो किसी भी प्रकार के टकराव असमानता बढ़ाते हैं और बहुपक्षीय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। लिहाजा यदि आगे की सही राह निकालनी है तो देर सबेर बहुपक्षवाद को मजबूत कर वित्त, तकनीक और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए देश-दुनिया के नेताओं को राष्ट्रीय हित से ऊपर उठकर वैश्विक साझेदारी अपनानी चाहिए। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए न केवल समुचित मंच प्रदान करती हैं, बल्कि ये शांति, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में देशों को परस्पर एकजुट भी करती हैं। मसलन, ऐसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और उनकी भूमिकाएँ देश-दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। ख़ासकर जहां संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति, सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए कूटनीतिक संवाद और संकट प्रबंधन करता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) महामारी नियंत्रण और स्वास्थ्य नीतियों में वैश्विक समन्वय स्थापित करता है। जबकि विश्व व्यापार संगठन (WTO) व्यापार नियमों से आर्थिक सहयोग बढ़ाता है। इसी प्रकार से आर्थिक और पर्यावरणीय संस्थाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। जहां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक वित्तीय स्थिरता, गरीबी उन्मूलन और जलवायु अनुकूलन के लिए सहायता देते हैं। वहीं, आईपीसीसी (IPCC) जलवायु सहयोग पर वैज्ञानिक रिपोर्ट साझा करता है। कुलमिलाकर ये वैश्विक संस्थाएँ संकटों में संसाधन जुटाकर और नीतियाँ बनाकर सहयोग को प्रभावी बनाती हैं। कहना न होगा देश-दुनिया के नीतिगत कदम जैसे पारदर्शिता, निरंतर संवाद और संयुक्त गतिविधियाँ देशों के बीच भरोसा बढ़ाते हैं। ये कदम टकराव कम कर सहयोग को मजबूत बनाते हैं। संवाद और कूटनीति यानी निरंतर बातचीत, जैसे 'पड़ोस पहले' नीति के तहत विवाद सुलझाना और हॉटलाइन स्थापित करना भरोसे का आधार बनाता है। जबकि ईमानदारी, गोपनीयता और पारस्परिक सम्मान वाली कूटनीति संबंधों को मजबूत करती है। जहां तक पारदर्शिता सम्बन्धी उपाय की बात है तो सैन्य विश्वास निर्माण उपाय (CBMs) जैसे हथियार नियंत्रण रिपोर्ट साझा करना, विदेशी सेना की जानकारी देना टकराव रोकता है। जबकि संयुक्त तथ्य-खोज मिशन और डेटा विनिमय जानकारी सममिति बढ़ाकर भरोसा जगाते हैं। वहीं सहयोगी पहलें के दृष्टिगत संयुक्त सैन्य अभ्यास, शांति रक्षा इकाइयाँ और आपदा राहत सहयोग एकजुटता दिखाते हैं। जबकि आर्थिक साझेदारी, सीमा समितियाँ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान गैर-पश्चिमी समाधानों को बढ़ावा देते हैं। अनुभव बताता है कि वैश्विक मुद्दों पर बहुपक्षीय सहयोग कई बार सफल रहा है, जहाँ देशों ने साझा लक्ष्यों के लिए एकजुट होकर ठोस परिणाम दिए। खासकर शांति, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों से, जिनका अपना महत्व हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह के मुताबिक, विश्व आर्थिक मंच, डावोस में वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी हॉवर्ड लुटनिक और डोनाल्ड ट्रंप के भाषणों का केंद्रीय संदेश साफ़ था कि यूरोप को चीन के "ख़तरे" से सावधान किया जाए। लेकिन यह चेतावनी जितनी ज़ोरदार थी, उतनी ही विवादित भी। क्योंकि चीन न तो अमरीका की तरह किसी देश पर हमला कर रहा है और न ही युद्ध की खुली धमकी दे रहा है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन चीन के आर्थिक और तकनीकी विकास से गहरी बेचैनी में दिखता है।

● कमलेश पांडेय

अजित पवार को सत्ता ... ललित गर्ग

अजित पवार: आरोपों से ऊपर उठे राजनीति के 'दादा-पुरुष'

यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया। जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है। अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा। इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे। बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे। "अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें?" जैसे बयान ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने माफी भी मांगी, सफाई भी दी और समय के साथ उन विवादों से उबरते हुए फिर सत्ता के शीर्ष पर लौटे। यह उनकी राजनीतिक जिजीविषा का प्रमाण था कि आलोचना और आरोप उन्हें रोक नहीं पाए।

शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चाएं रहीं। कभी मतभेद, कभी दूरी और कभी सियासी अलग राह की अटकलें। लेकिन अजित पवार स्वयं को हमेशा शरद पवार का अनुयायी बताते रहे। उन्हें मिला "दादा" का संबोधन केवल पारिवारिक नहीं था।

आलोचकों का ... राजेश जैन

यूजीसी के नए नियमः समानता की पहल या शिक्षा व्यवस्था में नया सामाजिक तनाव

उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफ़ा एक प्रशासनिक घटना भर नहीं है। यह उस गहरे असंतोष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर देश के एक बड़े वर्ग में उभर रहा है। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि ये नियम सामान्य वर्ग विरोधी हैं और छात्रों को संभावित अपराधी बना देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं, करणी सेना जैसे संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया और बहस सीधे कैंपस से सड़कों तक पहुंच गई। ऐसे में सवाल उठता है-क्या यूजीसी सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है या अनजाने में एक नया सामाजिक विभाजन खड़ा कर रहा है? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम अधिसूचित किए। इसके तहत हर सरकारी और निजी विश्वविद्यालय या कॉलेज में 'इक्विटी सेल' और 'इक्विटी कमेटी' बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सेल भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई करेगा और समिति की सिफारिश पर संस्थान को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इन नियमों का घोषित उद्देश्य है-धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकना। खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों को संरक्षण देना। यहां तक सब ठीक लगता है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ, जब जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी वर्ग को भी जोड़ दिया गया। पहले ड्राफ्ट में यह सुरक्षा केवल एससी और एसटी तक सीमित थी। अब ओबीसी भी इसके दायरे में आ गए हैं। यानी शिकायत करने वालों की सूची बढ़ गई, लेकिन आरोप झेलने वालों की पहचान लगभग तय हो गई-सामान्य वर्ग। नए नियमों के खिलाफ उठ रही आवाज़ों की जड़ में तीन बड़े डर हैं। पहला-सामान्य वर्ग को 'डिफॉल्ट आरोपी' बना दिया गया है। अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी छात्र शिकायत करता है, तो व्यवहारिक रूप से सामने वाला अधिकतर जनरल कैटेगरी से ही होगा। विरोधियों का कहना है कि अस्पष्ट जांच प्रक्रिया के चलते झूठे आरोप भी करियर तबाह कर सकते हैं। दूसरा-इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई अनिवार्यता नहीं है। समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं को शामिल करने की बात कही गई है, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई तय स्थान नहीं। इससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आलोचकों का कहना है-जब फैसला सभी पर लागू होगा, तो प्रतिनिधित्व कुछ वर्गों तक सीमित क्यों? तीसरा-भेदभाव की परिभाषा बेहद व्यापक रखी गई है। शब्द, व्यवहार और "अनुभूति" तक को शिकायत का आधार माना जा सकता है। ऐसे में झूठे मामलों का क्या होगा? दोष कैसे तय होगा? क्या सिर्फ महसूस करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा? डर यह है कि इससे कैंपस में अविश्वास का माहौल बनेगा। छात्र खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, शिक्षक संवाद से बचेंगे और शिक्षा का वातावरण डर-आधारित हो जाएगा।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने... वेदव्यास

30 जनवरी महात्मा गांधी शहीद दिवस पर विशेष यदि आज महात्मा गांधी जीवित होते

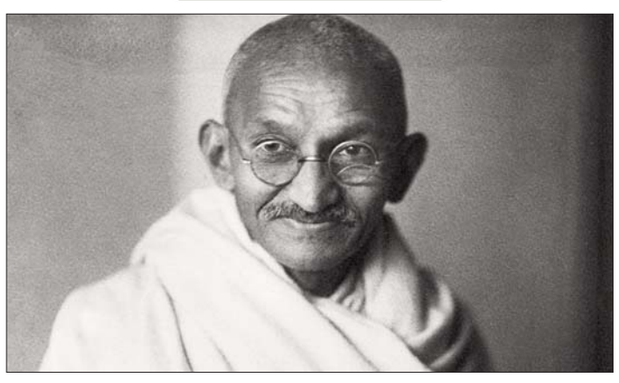

महात्मा गांधी भारत में लोकतंत्र के ऐसे देवता हैं कि संसद से लेकर सड़क तक, राजपथ से लेकर जनपथ तक, शौचालय से लेकर देवालय तक और व्यक्ति से लेकर विचार बनने तक, जीवन की हर एक प्रयोगशाला में अनिवार्य विषय के रूप में याद किए जाते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन का युद्ध विराम हो, हमारी समस्त ज्ञान चेतना में वह पंचतत्व की तरह प्रकृति और मनुष्य के बीच एक सेतु का काम करते हैं। कभी-कभी आश्चर्य होता है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई दूसरा महानायक हो जिसे संकटमोचक की तरह इस्तेमाल किया जाता हो। पिछले कुछ वर्षों से महात्मा गांधी भारत में स्वच्छता मिशन के राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं तो इससे पहले भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से जुड़े हुए रहे हैं। सरकारी बैंक के नोट (मुद्रा) से लेकर शासन-प्रशासन के हर कार्यस्थल पर इनका चित्र मौजूद है और शांति तथा युद्ध के हर मौसम में इन्हें याद किए बिना डिजिटल इंडिया का प्रत्येक कार्य अधूरा माना जाता है। विकास और परिवर्तन की, राष्ट्रवाद और लोकवाद की, भ्रम और यथार्थ की प्रत्येक दशा, दिशा और संभावना में गांधीजी के नाम का ताबीज बांधना देशवासियों की नित्य, क्रिया बन गई है। बहरहाल, महात्मा गांधी आज जीवित होते तो उन्हें पता चलता कि आजाद भारत के पुनर्निर्माण में वह एक भूमिपूजा से लेकर श्रीगणेश की भूमिका तक कैसे-कैसे व्याप्त है? महात्मा गांधी के नाम की इस ताकत को देखने-समझने से पता चलता है कि गांधीजी का अधिकतम उपयोग इस कालखंड में और भूमंडीकरण के पिछले 30 वर्षों के आर्थिक सुधारों में धीरे-धीरे एक ऐसा जुमला और टोटका बना दिया गया है ताकि उसका असल प्रभाव ही मजाक का विषय बन जाए। भारत में एक तरफ महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू की तो दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, शिवाजी, महाराणा प्रताप और सुभाषचंद्र बोस जैसी प्रेरणाओं की ऐसी मुक्तिवाहिनी सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं कि राजनीति के हर दंगल में भारत की अंतर-चेतना का आधार ही बदलता जा रहा है। भारत के इन निर्माताओं की जनता के मन में और खासकर युवा आबादी के दिल और दिमाग में शेष रहा-सहा प्रभाव, आदर्श और अनुसरण ही समाप्त होता जा रहा है। 1947 के बाद हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और अशफाक उल्ला जैसे सभी क्रांतिकारियों की परंपरा और योगदान को धीरे-धीरे ध्वस्त किया है तो 2014 के बाद हम-एक देश-एक बाजार, एक राष्ट्र-एक विचार, एक गांव-एक श्मशान और ऐसे ही अनेक प्रकार के नारों और दुष्प्रचारों के साथ स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण इतिहास-भूगोल और आधार को ही बदलने का ही प्रयास कर रहे हैं ताकि महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा, अंबेडकर का सामाजिक आर्थिक न्याय, जवाहरलाल नेहरू का वैज्ञानिक समाजवाद और कबीर, रैदास, नानक और अरविंद जैसों की विविधता में एकता की विरासत ही समाप्त हो जाए। भारत की परिभाषा को बदलने का यह दुष्परिणाम हो रहा है कि आज हम संवाद और सहिष्णुता की जगह युद्ध और मुठभेड़ का अभ्यास कर रहे हैं। जातिप्रथा के नाम पर दलित-आदिवासियों को न्याय और सम्मान से वंचित कर रहे हैं तो भारत माता, गौ माता और गंगा माता के हरि कीर्तिन में महिलाओं को सांस्कृतिक उत्पीड़न की दीवारों में कैद कर रहे हैं। यानी की जिसका जितना महिमामंडन हो रहा है वहां उसी का उतना ही खंडन और अवमूल्यन भी हो रहा है। हम महात्मा गांधी की मूल अवधारणा को ही नकारते हुए आज गांव, गरीब और स्वराज को ही नष्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत में लोकतंत्र की चाल, चेहरा और चरित्र बदला जा रहा है तथा आस्थाओं की राजनीति के तूफान में जाति-धर्म का उन्माद जगाया जा रहा है। महात्मा गांधी, अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू आज इसलिए भारत निर्माण की नई व्याख्याओं में हाशिए पर धकेले जा रहे हैं ताकि लोकतंत्र को एकाधिकारवादी, एकात्मवादी, राष्ट्रवादी और केवल और केवल संकीर्णवादी वर्ग और वर्ण चेतना में बदला जा सके। महात्मा गांधी आज भारत के राजतंत्र में कहीं भी नहीं हैं लेकिन प्रचार और दिखावे में सभी जगह है। आज गांधीजी का गुजरात ही इस बात का उदाहरण बना हुआ है कि दलितों पर गौरक्षकों के हमले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की घेराबंदी हो रही है तो पूरा भारत ही जातीय राजनीति की धार्मिक महाभारत में कौरव-पांडवों की तरह अच्छे दिनों की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में सोचने और समझने की बात यही है कि भारत का एक मोर्चा सीमा के पार है तो दूसरा मोर्चा घर के भीतर खुला हुआ है। महात्मा गांधी ने तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत से उखाड़ फेंका था लेकिन हम पिछले 77 साल में भी अपने पड़ोसी देशों से भाईचारा नहीं बना पा रहे हैं और दलित-अल्पसंख्यकों को न्याय और सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। महात्मा गांधी आज भारत की जाति-धर्म की राजनीति में सबसे पहले और अंतिम शहीद हैं क्योंकि हमने गांधीजी को शौचालय से देवालय तक स्थापित कर दिया है और साबरमती से राजघाट तक पहुंचा दिया है। (लेखक साहित्य मानीषी एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं) जवाहरलाल नेहरू का वैज्ञानिक समाजवाद और कबीर, रैदास, नानक और अरविंद जैसों की विविधता में एकता की विरासत ही समाप्त हो जाए। भारत की परिभाषा को बदलने का यह दुष्परिणाम हो रहा है कि आज हम संवाद और सहिष्णुता की जगह युद्ध और मुठभेड़ का अभ्यास कर रहे हैं। जातिप्रथा के नाम पर दलित-आदिवासियों को न्याय और सम्मान से वंचित कर रहे हैं तो भारत माता, गौ माता और गंगा माता के हरि कीर्तिन में महिलाओं को सांस्कृतिक उत्पीड़न की दीवारों में कैद कर रहे हैं।

खराब दौर और मानसिक दबाव के बीच युवराज ने खुद से किए कई सवाल

सम्मान-समर्थन नहीं मिलने के कारण लिया था संन्यास : युवराज

दिल्ली, एजेंसी

क्रिकेटर युवराज सिंह ने जून 2019 में क्रिकेट से संन्यास लेने के पीछे की असली वजह बताई है। युवराज ने सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें उस समय न खेल में खुशी मिल रही थी, न ही टीम मैनेजमेंट और माहौल से वह सम्मान, जिसके वे हकदार थे। 44 साल के युवराज ने कहा, 'मैं अपने खेल का आनंद नहीं ले पा रहा था। जब मजा ही नहीं आ रहा था, तो खुद से सवाल करने लगा कि आखिर क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। सपोर्ट और सम्मान की कमी भी महसूस हो रही थी।' युवराज ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 30 जून 2017 को खेला था। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे मैच में

39 रन बनाए थे। IPL में उनका आखिरी सीजन 2019 रहा, जिसमें वे मुंबई इंडियंस के साथ थे। युवी को इस सीजन में ज्यादा मैच खेलने को नहीं मिले थे। युवराज ने माना कि जब आप मानसिक रूप से खेल का लुत्फ उठाना बंद कर देते हैं, तो मैदान पर प्रदर्शन करना और भी कठिन हो जाता है। वनडे वर्ल्ड कप 2011 में युवराज सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। उन्होंने 8 पारियों में 90.50 की औसत से कुल 362 रन बनाए थे, जिसमें चार अर्धशतक और एक शतक शामिल था। उन्होंने टूर्नामेंट में 15 विकेट भी झटके थे। युवराज टूर्नामेंट में चार बार प्लेयर ऑफ द मैच बने और अंत में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था युवराज सिंह ने साफ किया कि संन्यास लेने के बाद उन्हें मानसिक शांति मिली। उन्होंने माना कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन सही समय पर रुकना भी जरूरी होता है। टूर्नामेंट के बाद

> **युवराज ने कहा, 'मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था। यह सोचकर परेशान था कि मैं क्या साबित करने के लिए खेल रहा हूं। जिस दिन मैंने क्रिकेट छोड़ा, उसी दिन मुझे लगा कि मैंने फिर से खुद को पा लिया है।'**

वर्ल्ड कप 2019 में चयन न होना टर्निंग पॉइंट बना

युवराज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग दोनों से उस समय संन्यास लिया, जब उन्हें 2019 में वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। उन्हें टीम में नंबर-4 स्लॉट के लिए चुने जाने की चर्चा थी। युवराज को भी अपने अनुभव के आधार पर उम्मीद थी, लेकिन चयन न होने के बाद उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संन्यास का ऐलान कर दिया।

एक क्रिकेटर ने पिता से कहा था कि युवराज में प्रतिभा नहीं है

युवराज ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनकी काबिलियत पर शक किया गया था। उन्होंने बताया, 'जब मैं 13-14 साल का था, तब एक सीनियर खिलाड़ी (जो उस समय टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे) ने मेरे पिता से शायद औपचारिकता में कुछ कह दिया था। उन्हें लगा होगा कि मुझमें उतनी प्रतिभा नहीं है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, लेकिन मेरे पिता को यह बात बहुत बुरी लगी थी।'

युवराज को कैंसर होने का पता चला, जिसके बाद उनका इलाज चला। इसके बाद वे एक साल से ज्यादा समय तक टीम इंडिया से बाहर रहे।

अभिषेक शर्मा लगातार 6 महीने से टी-20 के टॉप बैटर

कप्तान सूर्या की एक महीने बाद टॉप-10 में वापसी, ऑलराउंडर्स में हार्दिक तीसरे नंबर पर

दिल्ली, एजेंसी

टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ICC की रैंकिंग में लगातार छह महीने से नंबर वन बैटर बने हुए हैं। बुधवार को जारी रैंकिंग में 929 अंकों के साथ वह नंबर वन पर हैं। अभिषेक पहली बार 30 जुलाई 2025 को नंबर-1 बैटर बने थे। अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी-20 सीरीज के पहले मैच में 84 और तीसरे 68* रन की पारी खेली थी। वहीं, टीम इंडिया के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर टॉप-10 में जगह बना ली है। इस हफ्ते उन्हें पांच स्थान का फायदा मिला है। वह 717 रेटिंग अंकों के साथ सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। सूर्या दिसंबर पर टॉप-10 से बाहर हुए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पिछले दो मैचों में सूर्या ने लगातार दो अर्धशतक लगाए थे और दोनों मैच में नाबाद रहे भारत के तिलक वर्मा 781 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पंड्या तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। टी-20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से ठीक 10

दिन पहले यह भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है, जिससे टीम इंडिया को बड़ा मनोबल मिला है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी-20 बॉलर्स रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाई है। तीसरे टी-20 मुकाबले में कीवी टीम के खिलाफ तीन विकेट लेने के बाद बुमराह अब 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं, वरुण चक्रवर्ती पहले दो मैचों में कुल तीन विकेट लेकर रैंकिंग में पहले नंबर पर बने हुए हैं।

फास्ट न्यूज

भारती सिंह ने दूसरे बेटे का नामकरण किया

मुंबई। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके राइटर-एंकर पति हर्ष लिम्बाचिया हाल ही में दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। कपल ने बुधवार को अपने दूसरे बेटे के लिए नामकरण सेरेमनी का आयोजन किया। इस खास मौके की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने लाडले का नाम भी रिवील किया। भारती और हर्ष ने इंस्टाग्राम पर नामकरण सेरेमनी की तस्वीरें करते हुए कैप्शन में यशवीर लिखा।

ब्रिटिश पीएम 8 साल बाद चीन पहुंचे

बीजिंग। ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर बुधवार को 8 साल बाद तीन दिन के दौरे पर चीन पहुंचे। इससे पहले 2018 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे चीन पहुंची थी। पिछले 8 सालों में ग्लोबल राजनीति काफी बदल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रमक नीतियों और बयानों की वजह से यूरोपीय देश नए पार्टनर तलाश रहे हैं, ऐसे में चीन उन्हें एक मजबूत विकल्प नजर आ रहा है। चीन रवाना होने से पहले स्टार्मर ने मीडिया से कहा था कि ब्रिटेन को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के साथ रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन चीन को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी। ब्रिटेन भले ही आज चीन को जरूरी देश बता रहा है।

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 29 जनवरी को तेजी है। सेंसेक्स करीब 200 अंक की तेजी के साथ 82,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 70 अंक की तेजी है, ये 25,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। हालांकी आज ऑटो, FMCG और IT शेयर्स में गिरावट है। 28 जनवरी को विदेशी निवेशकों(FIIs) ने 880 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। वहीं घरेलू निवेशकों (DII) ने 3,057 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे हैं।

रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर

चावुंडी दैव परंपरा और हिंदू भावनाओं के अपमान का आरोप

मुंबई। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में बुधवार को बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाओं और कर्नाटक की चावुंडी दैव परंपरा का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) से जुड़ा है। रणवीर सिंह के खिलाफ यह एफआईआर बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर सिंह ने मंच पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और ऐसा अभिनय किया, जिससे दैवा परंपरा के पवित्र तत्वों का मजाक उड़ाया गया। शिकायत में कहा गया है कि रणवीर ने पंजुरली और गुलिगा दैवा से जुड़े भाव-हावभाव की नकल की और उन्हें भद्दे, हास्यास्पद और अपमानजनक तरीके से

प्रस्तुत किया। इसके अलावा अभिनेता पर चावुंडी दैव को 'महिला भूत' कहने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, चावुंडी दैवा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूजनीय रक्षक देवी मानी जाती हैं और वे दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक हैं। उन्हें 'भूत' कहना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है। अब यह मामला बेंगलुरु की प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (CMM) अदालत को भेज दिया गया है।

आर्यन खान की सीरीज के खिलाफ याचिका खारिज, शाहरुख खान से मांगा था 2 करोड़ का मुआवजा

समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका

मुंबई। आर्यन खान ड्रग केस के जांच अधिकारी रहे समीर वानखेड़े को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करने का उसके पास अधिकार नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि समीर वानखेड़े चाहें तो उचित अदालत में दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। अंतरिम याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने दो अहम सवालों पर विचार किया। समीर वानखेड़े की वकील जे. साई दीपक ने दलील दी थी कि यह मामला दिल्ली में सुनवाई योग्य है। उन्होंने कहा कि वानखेड़े से जुड़े विभागीय मामले दिल्ली में लंबित हैं और उनके खिलाफ खबरें प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थान, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस भी दिल्ली में स्थित हैं। दीपक ने यह भी कहा कि इस मामले में पहले से ही दोनों पक्षों के बीच विवाद रहा है। उनके अनुसार, जिस व्यक्ति को पहले

गिरफ्तार किया गया था, वही इस सीरीज का निर्देशक है और सीरीज के एक सीन में सीधे तौर पर समीर वानखेड़े को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि सीरीज निर्माताओं की नाराजगी और बदले की भावना का सीधा संबंध उस कथित मानहानि से है, जिसका सामना वानखेड़े को इस कंटेंट की वजह से करना पड़ा। समीर वानखेड़े ने इस मुकदमे में 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा था। उनका कहना था कि वह इस राशि को टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान करना चाहते हैं। इस रेड के चलते समीर वानखेड़े भी जांच के दायरे में आ गए थे। उस समय उनकी और शाहरुख खान के बीच हुई चैट भी पेश की गई थी। चैट में शाहरुख, समीर वानखेड़े से मदद मांग रहे थे।

> **दरअसल, सीरीज बॉलीवुड बैकड्रॉप पर बनी है। इसके पहले एपिसोड में दिखाया गया है बॉलीवुड सेलेब्स एक सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने हैं, जिसके बाहर एक अधिकारी को ड्रग का सेवन कर रहे लड़के को गिरफ्तार करते दिखाया गया है। इस किरदार को समीर वानखेड़े से काफी मिलता-जुलता दिखाया गया है। सीरीज जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर भी उस किरदार की तुलना समीर वानखेड़े से हुई थी।**

आर्यन खान के ड्रग केस में जांच अधिकारी थे समीर वानखेड़े

2 अक्टूबर 2021 में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गोवा जा रहे कोर्डिएला क्रूज से आर्यन खान और उनके दोस्तों को ड्रग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की टीम, पैसेंजर बनकर शिप पर चढ़ी। रात 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली छापेमारी में कोकीन और चरस सहित दूसरे ड्रग्स बड़ी मात्रा में जब्त किए गए। आर्यन खान को इस मामले में कई हफ्तों तक आर्थर रोड जेल में रखा गया था। जमानत के कागजात में देरी के कारण आर्यन 30 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से रिहा हुए।

उइगर मुसलमानों के हिरासत कैंप की वीडियो बनाई थी, जज बोले- वापस भेजने पर जान का खतरा

चीन की पोल खोलने वाले नागरिक को अमेरिका में शरण

वॉशिंगटन, एजेंसी

चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की पोल खोलने चीनी वाले नागरिक को अमेरिका में शरण मिल गई है। जज ने कहा कि अगर गुआन को चीन वापस भेजा गया तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, गुआन हेंग ने शिनजियांग इलाके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर किया था। उसने 2020 में हिरासत केंद्रों की छुपकर फिल्म बनाई थी। गुआन 2021 में गैरकानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा था। अगस्त 2025 में उसे हिरासत में ले लिया गया। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि शिनजियांग में दस लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा

गया है। चीन में उइगर मुसलमान अपने अस्तित्व के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चीनी सरकार ने 2014 से सरकारी नौकरी करने वाले उइगर मुसलमानों के सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने और दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाई हुई है। गुआन ने शिनजियांग इलाके के हिरासत केंद्रों की वीडियो फुटेज ली और पब्लिश करने के लिए चीन छोड़ दिया। गुआन ने अमेरिका पहुंचने से कुछ दिन पहले वीडियो जारी किया था।

दावा- चीन के कैंप से भागने वालों को गोली मारने का आदेश

कई रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकारी नौकरी करने वाले उइगरों को पांच वक्त की नमाज पढ़ने या रामजान में रोजा रखने पर सजा मिल सकती है, नौकरी जा सकती है। उइगर महिलाओं के बुर्का पहनने की भी मनाही है। चीन सरकार ने 2008 में दाढ़ी रखना बैन किया था। उइगर महिला पर्दा करके पेट्रोल स्टेशन, बैंक और हॉस्पिटल नहीं जा सकतीं। वह सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकतीं।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में कई पुलिस फाइलें मिली थीं। इनमें कैंपों के इस्तेमाल की डिटेल थी। इनमें हथियारबंद अधिकारियों का रुटीन बताया गया था। उन्हें भागने की कोशिश करने वालों के लिए गोली मारने तक का अधिकार दिया गया था। कैंपों से भागने वाले लोगों ने शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा की रिपोर्ट दी है।

खुद को चीनी नहीं मानते उइगर मुसलमान

उइगर एक तुर्क जातीय समूह है जो मुख्य रूप से शिंजियांग में रहता है। शिंजियांग की सीमा मंगोलिया और रूस सहित 8 देशों के साथ मिलती है। इस इलाके में मुस्लिम धर्म को मानने वाली उइगर जाति का काफी लंबे समय बीजिंग के साथ एक विवादास्पद संबंध रहा है। शिन्जियान प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमान खुद को चीनी नहीं मानते। वे तुर्किश भाषा बोलते हैं और खुद को तुर्की मूल का मानते हैं। इस क्षेत्र में उइगर और चीनी सुरक्षा बलों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं। कम्युनिस्ट सरकार की कठोर नीति के कारण हजारों उइगर भागकर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं।

सोना एक दिन में ₹11,486 बढ़कर ₹1.76 लाख पहुंचा

चांदी तीन दिन में ₹68,228 महंगी, ₹3.86 लाख हुई

नई दिल्ली, एजेंसी

चांदी-सोने के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रुपए बढ़कर 1,76,121 रुपए पर पहुंच गया है। तीन दिन में सोना 21,811 महंगा हुआ है। इससे पहले सोने का भाव 23 जनवरी को 1,54,310 रुपए/10g था। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 27,666 रुपए बढ़कर 3,85,933 रुपए किलो पर पहुंच गई है। तीन दिन में चांदी की कीमत 68,228 रुपए महंगी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत ₹3,17,705 रुपए किलो थी। इस साल अब तक सिर्फ 29 दिन में ही चांदी 1.55 लाख रुपए और सोना 43 हजार रुपए महंगा हो चुका है। IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता।

इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इस साल जनवरी के 29 दिन में ही सोने की कीमत 42,926 रुपए बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,33,195 रुपए का था, जो अब 1,76,121 रुपए हो गया है। वहीं, चांदी 1,55,513 रुपए महंगी हो गई है। 31 दिसंबर 2025 को एक किलो चांदी की कीमत 2,30,420 रुपए थी, जो अब 3,85,933 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है।

जानकारी : अमेरिका तेल बेचने से कमाए पैसे भेजेगा, अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी कतर को मिली

ट्रम्प को हर महीने बजट का हिसाब देगी वेनेजुएला सरकार

वॉशिंगटन, एजेंसी

वेनेजुएला की अंतरिम सरकार हर महीने अमेरिका को बजट का हिसाब देगी। यानी कि उन्हें यह बताना होगा कि महीनेभर में उसे पैसे कहां-कहां खर्च करने हैं। इसके बदले में अमेरिका उस पैसे को रिलीज करेगा, जो वेनेजुएला के तेल बेचने से मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह जानकारी बुधवार को संसद में दी। रुबियो ने बताया कि अभी शुरुआत में यह पैसा जिस खाते में रखा जाएगा, उसे कतर संभालेगा इसपर डेमोक्रेट सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि कतर वेनेजुएला से हजारों मील दूर है

और यह साफ नहीं है कि यह व्यवस्था कानूनी और पारदर्शी कैसे है। उन्होंने यह भी कहा कि कतर के शासक को राष्ट्रपति ट्रम्प का करीबी माना जाता है, इसलिए शक और बढ़ता है। रुबियो ने कहा कि कतर को पैसा भेजना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध हैं। इसके अलावा अगर पैसा सीधे आया तो वेनेजुएला को पैसा देने वाले अमेरिकी लोग उस पर कानूनी दावा कर सकते हैं। ये वही ऊर्जा कंपनियां हैं जिनकी संपत्ति करीब 20 साल पहले वेनेजुएला ने जब्त कर ली थीं। वहीं, रुबियो ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला राष्ट्रपति की गिरफ्तारी किसी तरह का एक्ट ऑफ वॉर नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत की गई कार्रवाई थी।

रुबियो बोले- हमारा मकसद वेनेजुएला में गृह युद्ध रोकना था

अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो ने कहा है कि वेनेजुएला की स्थिति अस्थिर थी और उसे बचाना जरूरी था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिका के तीन उद्देश्य थे, जिनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसे इन्फेक्शन को खत्म करना था जिसके बाद एक वेनेजुएला डेमोक्रेटिक बने।

सीनेटर ने ऑपरेशन के खर्च पर सवाल उठाए

सुनवाई के दौरान डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन ने इस ऑपरेशन के खर्च पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई और समुद्री नाकेबंदी पर करीब 1 अरब डॉलर खर्च हो सकता है। शाहीन ने कहा कि उनके मतदाता पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति महंगाई और रोजमर्रा की दिक्कतों के बजाय वेनेजुएला पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने पूछा कि क्या यह ऑपरेशन युद्ध जैसा है। लेकिन रैंड पॉल ने इन दलीलों को खोखला बताकर खारिज कर दिया। हालांकि जरूरत पड़ने पर अपने हितों की रक्षा से इनकार भी नहीं किया।

अमेजन 16,000 और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी

कुल 30,000 ऑफिस वर्कर्स की छंटनी होगी, 2023 के बाद सबसे बड़ा लेऑफ

नई दिल्ली, एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बुधवार को 16,000 और कर्मचारियों की छंटनी करने का एलान किया है। यह पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुई रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। उस समय कंपनी ने 14,000 पदों को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब कुल छंटनी का आंकड़ा बढ़कर 30,000 हो गया है। अमेजन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेथ गैलेटी ने एक बयान में कहा कि इन नौकरियों में कटौती का मकसद मैनेजमेंट की लेयर्स को कम करना, जिम्मेदारी बढ़ाना और कंपनी के भीतर ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना है। कंपनी चाहती है कि उसके कर्मचारी तेजी से फैसले ले सकें और ग्राहकों के लिए नए इनोवेशन करने की क्षमता बढ़ा सकें। अमेजन में कोरोना महामारी के बाद 2022-2023 में हुई

27,000 कर्मचारियों की छंटनी के बाद यह सबसे बड़ी कटौती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह छंटनी मुख्य रूप से अमेजन के कॉर्पोरेट और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। अमेजन के दुनिया भर में करीब 3.5 लाख ऑफिस कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 10% यानी 30,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि उसके वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में काम करने वाले 15 लाख कर्मचारियों पर इस कटौती का कोई असर नहीं होगा। अक्टूबर में जब पहली बार छंटनी की खबरें आई थीं, तब कंपनी ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया था। जानकारों का कहना है कि अमेजन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी अपनी वर्कफोर्स को इसी हिसाब से एडजस्ट कर रही है। बुधवार को कंपनी ने कहा कि हर टीम लगातार अपनी क्षमता का मूल्यांकन करेगी और जहां जरूरत होगी, वहां बदलाव किए जाएंगे। अमेजन ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किस विभाग से कितने लोग निकाले जाएंगे। कंपनी 6 फरवरी 2025 को अपने पूरे साल के वित्तीय नतीजे पेश करेगी। इसी दौरान एक लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए छंटनी और भविष्य के प्लान को लेकर और अधिक जानकारी दी जा सकती है।

एलडीए बनाएगा 27 मंजिला अपार्टमेंट

1900 वर्गफीट के होंगे 384 लग्जरी फ्लैट, रजिस्ट्रेशन शुरू, कीमत ₹1.11 करोड़

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) शहरवासियों को एक और बड़ी आवासीय सौगात देने जा रहा है। ऐशबाग इलाके में एलडीए 27 मंजिला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऐशबाग स्क्वायर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 1900 वर्गफुट क्षेत्रफल के 384 लग्जरी फ्लैट्स होंगे। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। फ्लैटों के लिए 29 जनवरी से 28 फरवरी तक पंजीकरण किया जा सकेगा। पंजीकरण केवल एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से होगा। फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह राशि 2.5 प्रतिशत रखी गई है। फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार ऐशबाग स्क्वायर की

लोकेशन शहर के लिहाज से बेहद प्राइम है। यह पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनेगा, जहां बड़े आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मिलना मुश्किल होता है। यहां से चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, साथ ही नाका, अमीनाबाद और आलमबाग जैसे प्रमुख बाजार बेहद करीब होंगे। ऐशबाग स्क्वायर का निर्माण 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, 5 वर्ष के भीतर आवंटियों को फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा। आवंटन के बाद फ्लैट की राशि 36 महीनों की किश्तों में जमा करनी होगी।

ऑनलाइन डिमांड सर्वे के बाद मिली मंजूरी

विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि सोसाइटी में स्विमिंग पूल पार्क क्लब हाउस किड्स प्ले एरिया पावर बैकअप 600 से अधिक वाहनों की पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिसर में कॉमर्शियल दुकानें भी बनाई जाएंगी।

अगर कोई आवंटी 45 से 90 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करता है, तो उसे 4 से 6 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ऑनलाइन डिमांड सर्वे कराया गया था। सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही परियोजना को अंतिम मंजूरी दी गई। करीब 17,910 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले ऐशबाग स्क्वायर में 27 मंजिला के कुल 4 टावर होंगे। इसमें 3 बीएचके के प्लस स्टडी श्रेणी के 384 फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्गफुट होगा और कीमत 1.11 करोड़ रुपए से शुरू होगी।

2 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें लखनऊ डायवर्ट

सरोजनी नगर, लखनऊ। काठमांडू में खराब मौसम के कारण गुरुवार सुबह 2 उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। ये उड़ानें कुवैत और शारजाह से काठमांडू जा रही थीं, लेकिन वहां लैंडिंग नहीं कर सकीं। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, काठमांडू में घना कोहरा और कम विजिबिलिटी के कारण विमानों की लैंडिंग प्रभावित हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने सुरक्षा कारणों से विमानों को उतरने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि कुवैत से काठमांडू जा रही जजीरा एयरलाइंस की उड़ान संख्या J9539 को सुबह 6:40 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। इस विमान में 169 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम अनुकूल होने के बाद विमान को काठमांडू के लिए रवाना किया जाएगा। इसी क्रम में, शारजाह से काठमांडू जा रही एयर अरेबिया की उड़ान संख्या G9536 को भी काठमांडू में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। यह विमान काठमांडू एयरपोर्ट के ऊपर कई चक्कर लगाने के बाद सुबह 7:40 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। इस उड़ान में 167 यात्री सवार थे। खराब मौसम का असर लगातार अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर देखा जा रहा है।

अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा

1 किमी तक सुनाई दिया धमाका, दुकानदार झुलसा

- पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। बीबीडी थाना क्षेत्र के जुग्गौर इलाके में गुरुवार सुबह अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलिंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में दुकानदार करन गंभीर रूप से झुलस गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज करीब एक किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। धमाके के बाद आसपास के मकानों से लोग बाहर निकल आए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार,

जुग्गौर इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। कई बार इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बीबीडी थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के समय दुकान में केवल करन ही मौजूद था। अवैध गैस रिफिलिंग से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

फास्ट न्यूज

बेडरूम से निकलीं भैंस-बकरी

लखनऊ। लखनऊ में एक घर के बेडरूम से भैंस-बकरी निकलने लगीं। यह अजीब बात नहीं बल्कि नगर निगम टीम के एक्शन के दौरान हुई घटना है। दरअसल, नगर निगम की टीम जोन-8 के बिजनौर में अवैध रूप से चल रहीं डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। टीम को देखते ही एक डेयरी वाले ने अपनी भैंस और बकरियों को घर के अंदर कमरे में बंद कर दिया।

होलिका दहन का चबूतरा तोड़ा, पार्षद से हाथापाई

आगरा। सार्वजनिक जगह पर ग्रामीणों ने चंदा करके होलिका दहन का चबूतरा बनवाया। नगर निगम की टीम ने उस चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर लोगों का आक्रोश भड़क गया। नगर निगम की टीम ने क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा से हाथापाई के साथ ही गाली-गलौज भी की। इससे क्षेत्र में आक्रोश भड़क गया है। वार्ड 77 शहीद नगर के पार्षद दीपक वर्मा का कहना है-बुधवार को नगर निगम की टीम ने चमरौली में खेलकूद के मैदान पर बने अस्थायी होलिका दहन के स्थल को तोड़ दिया। इस चबूतरे को ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। यह सार्वजनिक जमीन खेलकूद मैदान के नाम दर्ज है। पार्षद का कहना है-मोहल्ला चमरौली में होलिका दहन खेलकूद के नाम से जमीन पर 50-60 साल से होलिका दहन हो रहा है। 5-6 दिन पहले गांव के लोगों के लोगों ने मीटिंग हुई थी।

रोटरी क्लब मुरादाबाद ग्रेट ने मनाया 19वां चार्टर डे

मुरादाबाद। रोटरी क्लब मुरादाबाद ग्रेट ने सुगंध रेस्टोरेंट में अपना 19वां चार्टर दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर क्लब के पूर्व अध्यक्षों के सेवा कार्यों को सम्मानित किया गया और सदस्यों ने एक-दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद परि बेटी ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। पूर्व मंडलाध्यक्ष नीरज अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे, जबकि डॉ. गोविंद नौन्याल ने कार्यक्रम का संचालन किया।

डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा की उंगली तोड़ी

बहरू गांव के लोगों में गुस्सा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक भी प्रदर्शन में पहुंचे

तमसा संकेत, एजेंसी

दुबग्गा। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र स्थित बहरू गांव में असामाजिक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा की उंगली तोड़ दी। असामाजिक तत्वों की इस हरकत से ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया है। प्रतिमा को बुधवार रात से गुरुवार तड़के के बीच खंडित किया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखी तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण "जय भीम" के नारे लगाते हुए घटनास्थल पर जमा हो गए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही काकोरी कोतवाली पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल भी पहुंच गईं। ये दोनों पति-पत्नी हैं। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी शकील अहमद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही नई प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी।

पुलिस के समझाने के बावजूद लोग अड़े रहे

लोगों ने पुलिस से नई प्रतिमा की तत्काल स्थापना, प्रतिमा स्थल पर बाउंड्री निर्माण, स्थायी बिजली व्यवस्था, CCTV कैमरे लगाने और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी मांग रखी। ग्रामीणों ने यह मांग की है बुद्ध पार्क के पास स्थित देसी शराब की दुकान को हटाया जाए।

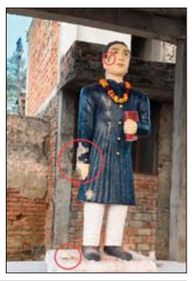

मैदान में खेल रहे बच्चों ने खंडित प्रतिमा देखी

जानकारी के अनुसार, गुरुवार की सुबह मैदान में खेल रहे बच्चों ने मूर्ति टूटी हुई देखी, जिसके बाद उन्होंने गांव वालों को सूचना दी। यह खबर फैलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने मूर्ति स्थल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची काकोरी पुलिस को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के समझाने के बावजूद ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे।

पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए काकोरी, दुबग्गा, पारा और मानक नगर थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है।

कई दलों-संगठनों के नेता-पदाधिकारी पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अजय देवा, शैलेंद्र आजाद, निशांत गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अयोध्या जेल की दीवार तोड़कर 2 कैदी भागे

स्पेशल सेल में बंद थे, रातभर में 30 ईंट उखाड़ी, जेलर समेत 7 सस्पेंड

तमसा संकेत, एजेंसी

अयोध्या। अयोध्या जिला जेल से दो कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए। दोनों स्पेशल सेल में बंद थे। दोनों ने रातभर में सेल की पीछे की दीवार की 25-30 ईंटें उखाड़ीं। भागकर जेल की बाउंड्री वॉल तक गए। फिर कंबल और मफलर से रस्सी बनाकर 20 फीट ऊंची दीवार फांद गए। कैदियों के भागने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज और शेर अली उर्फ रफीक अली के रूप में हुई है। गोलू अमेठी और रफीक सुलतानपुर का रहने वाला है। दोनों हत्या और रेप के आरोप में बंद थे। डीजी जेल पीसी मीणा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल के वरिष्ठ अधीक्षक यूपी मिश्रा, जेलर जेके यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, एक हेड वार्डर और तीन वार्डर को सस्पेंड कर दिया। विभागीय

जांच के आदेश भी दिए। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर जिला जेल पहुंचे। जेल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक, दोनों कैदी जेल की स्पेशल सेल नंबर-एक की 4 नंबर कोठरी में बंद थे। बुधवार की शाम 6 बजे बैरक को बंद किया गया। उस वक्त तक दोनों कैदी बैरक में ही थे। आज सुबह यानी गुरुवार सुबह 6 बजे कैदियों की गिनती शुरू हुई। इसमें कैदियों को नाम बुलाया गया तो दोनों कैदी नहीं मिले।

धूप को बेअसर कर रही पछुआ हवा

लखनऊ। लखनऊ में बुधवार की बारिश के बाद गुरुवार सुबह बादल छाए रहे। इससे ठंड बढ़ गई। 9 बजे तक में धूप निकल आई, लेकिन तेज पछुआ हवा भी चलने लगी। 20 किमी प्रति घंटे से भी तेज चली हवा से धूप बेअसर रही। सर्द हवा से ठंड का अहसास दोपहर में भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 दिन तक मौसम इसी तरह अस्थिर बना रहेगा। आज से मौसम में हल्का सुधार आता जाएगा। अनुमान है कि 2 फरवरी से मौसम एकदम साफ हो जाएगा। इस हवा के कारण वातावरण में नमी कम हो रही है और ठंड का असर तेज हो रहा है आज सुबह लखनऊ के बाहरी और गोमती किनारे वाले इलाकों में हल्का कोहरा भी देखने को मिला। आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार शाम या रात होते-होते बादलों में आंशिक कमी आ सकती है। गुरुवार से मौसम के धीरे-धीरे साफ होने की संभावना है, लेकिन ठंड में बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी।आगले तीन दिनों तक सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई गई है।

एकतरफा प्यार में युवती पर सर्जिकल ब्लेड से हमला

कानपुर में कलाई और चेहरे पर 13 वार किए, 9 दिन बाद शादी है

- मोहल्ले के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।
- भीड़ ने आरोपी युवक गोलू की जमकर पिटाई कर दी। फिर पुलिस के हवाले किया।

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में एकतरफा प्यार में युवक ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया। चेहरे और कलाई पर 13 वार किए। वह दर्द से कराहने लगी। चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े। आरोपी को पकड़ लिया और पीट-पीट की अधमरा कर दिया। फिर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, युवती को घरवालों ने हैलट में भर्ती कराया है।

गुस्साए घरवाले और लोगों ने कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में हंगामा किया। परिजनों ने बताया कि 9 दिन बाद, 7 फरवरी को युवती की शादी होनी है। मामला बुधवार देर शाम नजीराबाद थाना क्षेत्र का है। नजीराबाद थाना क्षेत्र के भदौरिया चौराहा इलाके में रहने वाली 24 वर्षीय युवती के परिवार में माता-पिता, दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी है। लड़की का भाई ठेला लगाता है। परिजनों ने बताया कि उनके घर के पास एल्युमिनियम कारखाना है। फैक्ट्री में बीते दो साल से गोलू नाम का युवक काम करता है। गोलू का लड़की के घर आना-जाना था। युवती ने बताया कि बुधवार देर शाम गोलू आया और उसने रेस्टोरेंट चलकर खाना खाने की बात कही। गोलू नशे में था। इस वजह से लड़की ने इनकार कर दिया और अपने घर जाने को कहा। आरोप है कि इस पर गोलू ने सर्जिकल ब्लेड से चेहरे और कलाई पर करीब 13 बार हमला कर दिया। युवती ने काफी संघर्ष कर खुद को बचाने की कोशिश भी की। युवती दोनों हाथ और चेहरे पर कई जगह ब्लेड लगने से लहुलूहान हो गई। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े और गोलू को जमकर पीटा। हंगामे की सूचना पर नजीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची।

झांसा : कानपुर में शादी के झांसे में लड़की ने गहने-कैश दिए, मांगने पर ब्लैकमेल किया, आरोपी अरेस्ट

फर्जी आईएएस बनकर युवती से 71 लाख वसूले

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में एक युवती को शातिर युवक ने पहले खुद को सरकारी बैंक का अधिकारी बताकर प्रेमजाल में फंसाया। इसके बाद IAS में सिलेक्शन होने की बात कही। लड़की से शादी करने का झांसा दिया। सिलेक्शन के नाम पर लाखों रुपए की जरूरत होने की बात कही। रुपए मांगे। इस पर लड़की ने करीब कैश और गहने मिलाकर करीब 71 लाख रुपए दे दिए। शातिर युवक ने सरकारी विभाग की वेबसाइट जैसी मेल आईडी से फर्जी ई-मेल, जॉइनिंग लेटर और डॉक्यूमेंट वॉट्सऐप पर भेजकर IAS में जॉइनिंग का भरोसा दिलाया। पुलिस ने आरोपी नीतेश पांडेय को अरेस्ट कर लिया है। लड़की के भाई ने बताया- दुकान और बहन की शादी के लिए जुटाकर रुपए रखे थे। गहने भी बहन के पास ही थी। शातिर नीतेश पांडेय ने शादी का झांसा दिया। IAS में सिलेक्शन के नाम पर लाखों रुपए

- कल्याणपुर थाना पुलिस ने आरोपी नीतेश पांडेय को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा।

मांगे। बहन ने घर में रखे गहने और कैश दे दिए। नीतेश ने पहले 26.50 लाख रुपए कैश लिए। इसके बाद करीब 45 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर भी हड़प लिए। नीतेश ने झांसा दिया कि IAS की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शादी करेगा।

26.50 लाख कैश और 45 लाख के गहने लिए

कल्याणपुर निवासी युवती एक मीडिया संस्थान में काम करती थी। पिता नगर निगम में क्लर्क हैं। उसके दो भाई हैं। मां की मौत हो चुकी है। भाई ममता आर्टिफिशियल के नाम से दुकान चलाते हैं। मां की मौत के बाद लड़की ही घर के पैसे और गहने वगैरह रखती थी।

चाकू दिखाकर धमकाया, फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कही

आरोप है कि जब युवती ने रुपए मांगे और पुलिस में केस करने की बात कही तो युवक नीतेश ब्लैकमेल करने लगा। जान से मारने की धमकी दी। निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। 14 अक्टूबर 2025 को युवती दिवाकर मिश्रा उर्फ सत्यम के घर गई थी। आरोप है कि यहां नीतेश पांडेय ने चाकू दिखाकर धमकाया। गालियां दी। पूरे परिवार को जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दिया।

पीड़ित युवती ने बताया- शुक्लागंज के दिवाकर मिश्रा उर्फ सत्यम परिवारिक मित्र हैं। उन्हीं के माध्यम से चकेरी निवासी नीतेश पांडेय से मुलाकात हुई। नीतेश ने खुद को पहले सरकारी बैंक में फील्ड ऑफिसर बताया, फिर एसडीएम और बाद में आईएएस में चयन का दावा किया।

अलंकार अग्निहोत्री देर रात बरेली से लखनऊ लाए गए

ससुराल में बोले- बजरंगबली का आशीर्वाद मेरे साथ, सुरक्षा नहीं मांगूंगा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को बुधवार देर रात लखनऊ लाया गया। उन्होंने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। उन्हें आलमबाग में उनकी ससुराल में ड्रॉप किया गया, जहां रात में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। लखनऊ पहुंचने पर PCS अधिकारी अलंकार ने पत्रकारों से कहा- बजरंगबली का आशीर्वाद मेरे साथ है। सुरक्षा नहीं मांगूंगा। उन्होंने आगे कहा- बरेली प्रशासन ने सुनियोजित तरीके से लखनऊ भेजा है। मौखिक आदेश पर मुझे जिलाबदर कर दिया गया। बरेली में ऐसा कोई ठोस घटनाक्रम नहीं था, जिसकी वजह से मुझे वहां से हटाने की जरूरत पड़ती। सरकार को अधिकार है कि वह इस्तीफा मंजूर करे या न करे, लेकिन मुझे जानबूझकर बरेली में नहीं रहने दिया गया। इस बीच उनका नया ट्वीट सामने आया है। इसमें उन्होंने सभी सामान्य वर्ग के संगठनों, सर्व समाज और विभिन्न किसान यूनियनों से एकजुट

होने की अपील की है। उन्होंने X पर लिखा- 'अब एक ऐसे नए विकल्प पर विचार करने का समय आ गया है, जिसमें सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो।' लोग इसे हैशटैग #Mera_CM_Mera_Beta और #savarn_ekta के साथ तेजी से शेयर कर रहे हैं। बहन आस्था मिश्रा से अलंकार जीजा की शादी 2012 में हुई थी। पिता अशोक कुमार मिश्रा (अलंकार के ससुर) का वर्ष 2025 में निधन हो गया था। वह रेलवे में सीनियर सेक्शन के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। परिवार में दूसरा छोटा साला अभिजीत मिश्रा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।

पृष्ठ 01 का शेष...

12 लाख...

इस योजना पर सरकार का करीब 420 करोड़ रुपए खर्च आएगा योगी सरकार ने सीएम फेलोशिप वालों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने को मंजूरी दी। एक साल फेलोशिप वालों को लिखित परीक्षा में 1.5 अंक, दो साल वालों को 3 अंक और 3 साल वालों को 4.5 बोनस अंक दिए जाएंगे।

विजय चौक पर...

विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतों को रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। समारोह का समापन बिगुलरों द्वारा बजाई जाने वाली अमर धुन 'सारे जहां से अच्छा' के साथ हुआ। इस साल बीटिंग रिट्रीट की एक विशेषता यह है कि विजय चौक के सीटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। इनमें बांसुरी, डमरू, एकतारा, तबला, वीणा, सितार, शहनाई, संतूर, सरोद, पखावज, नगाड़ा और मृदंगम जैसे वाद्य शामिल हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के प्रतीक स्वरूप ये पहल की जा रही है। एक दिन पहले गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी और बेस्ट झांकी के नतीजों की घोषणा की गई। तीनों सेनाओं में इंडियन नेवी को बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी चुना गया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सहायक बलों की कैटेगरी में दिल्ली पुलिस को पहला स्थान मिला।

बजट सत्र से...

संसद में पीएम विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते। सदन के अंदर उनकी स्पीच चुनावी रैली जैसी होती है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को हुई थी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इससे पहले प्रश्नकाल खत्म हुआ। बजट सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को लोकसभा के कार्यवाही शुरू हुई। शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। उधर, राज्यसभा में अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों को संबोधित किया। पहला मुद्दा केरल के बागान (प्लांटेशन) क्षेत्र से संबंधित था, जिसे सीपीआई के संदोष कुमार पी ने उठाया। उन्होंने कहा कि इससे यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के खरीदारों का दिल जीत लेंगे। इसका प्रभाव दशकों तक रहेगा। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्तावित करता है।'

पार्टी में मतभेदों...

पीटीआई के अनुसार 19 जनवरी को कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर को नजर-अंदाज कर दिया था। थरूर के करीबी सूत्रों के मुताबिक यह घटना उनके लिए टिपिंग पॉइंट साबित हुई। इससे पहले भी राज्य के कुछ नेता उन्हें नजर-अंदाज करने की कोशिश कर चुके हैं, जिससे वह असहज महसूस कर रहे थे।

केकेसी में यूजीसी के नए नियमों का विरोध

छात्रों ने किया प्रदर्शन, कैंपस पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा

- छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के KKC कॉलेज में गुरुवार को छात्रों ने UGC के नए नियमों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों ने इसे देश के लिए खतरनाक बताते हुए इन कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। इस दौरान कॉलेज परिसर में नारेबाजी और विरोध मार्च के चलते माहौल काफी गरमाया रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि UGC का नया बिल देश के भविष्य को नष्ट कर रहा है। इससे एक वर्ग को जुल्म के नाम पर दूसरे के साथ नाइंसाफी करने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत उठाया गया कदम है। छात्रों ने यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में कॉलेज के LLB स्टूडेंट्स ने जोरदार विरोध दर्ज

कराया। उनका का कहना है कि नए बिल में सामान्य वर्ग के लोगों के अधिकारों को नष्ट कर दिया गया हैं। उनका आरोप है कि यह बिल संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है और इससे सामाजिक ताना बाना भी नष्ट हो रहा है। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर "UGC बिल वापस लो" और 'देश बचाओं' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन-कारियों ने कॉलेज परिसर में मार्च करते हुए पहले गेट पर आए और फिर रोड से वापस कैंपस में जाकर नारेबाजी करने लगे।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676